



Jilla Sahkari Krushi Aur Gramin Vikas Bank Rajnandgav Samasya, Uplabdhya Aur Sambhavnaye (2006-2011)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव समस्याएं, उपलब्धियां एवं सम्भावनाएँ (२००६-२०११)

* Dr. S. H. Bhatiya ** Dr. Harjindrapal Sing Saluja
*** Dr. Ravish Kumar Sony **** Sangita Sakvar Mehuriya

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शास. दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

** सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शास. विष्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

*** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)

**** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय भिलाई-३ (छ.ग.)

१. परिचय :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव जो पूर्व में जिला भूमि विकास बैंक राजनांदगांव के नाम से जाना जाता था का गठन १३ फरवरी १९७५ को हुआ था। दीर्घावधि के लिए कृषि ऋण प्रदान करना इस बैंक की विषिष्ट पहचान है। इस बैंक द्वारा ५ से २० वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण दिये जाते हैं।

इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजनांदगांव जिला है। यह बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से जिले के कृषकों को उनकी कृषि भूमि को बंधक रखकर उन्हें दीर्घावधि कृषि, ऋण प्रदान करता आ रहा है। बैंक द्वारा मुख्यतः नवीन कृषि निर्माण, पंप सैट, बैलजोडी, गाडी, डेयरी मछलीपालन, ट्रैक्टर, पावर टीलर, श्रेसर इत्यादि प्रयोजनो हेतु कृषकों को ऋण मुहैया कराया गया है। वित्तीय वर्ष २००९-२००२ से बैंक द्वारा अकृषि कार्यों जैसे मिनी ट्रक, छोटे आटो रिक्शा, ग्रामीण आवास, ईटा भट्टा, आयल मिल पोहा मिल, मिनी राइस प्लांट इत्यादि हेतु भी ऋण वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार इस बैंक द्वारा जिले के कृषि व ग्रामीण विकास हेतु कृषकों को कृषि के साथ अकृषि कार्यों हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

२. षोध के उद्देश्य :-

यह षोध कार्य निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।

१. बैंक द्वारा जिले के कृषकों को कृषि व अकृषि कार्यों हेतु प्रदत्त ऋणों के फलस्वरूप जिले के कृषकों की आय में हुई वृद्धि व प्रगति का आंकलन करना तथा देखना की यह पर्याप्त व संतोशजनक है या नहीं।
२. इस बात का अध्ययन करना ही क्या कृषक बैंक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है यदि नहीं तो किन बातों को लेकर उनमें असंतोश है व इस असंतोश को कैसे दूर किया जा सकता है।
३. बैंक को अपने कार्यों के संचालन में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
४. बैंक की समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी उपायों को प्रस्तुत करना जिससे बैंक की प्रगति सुनिश्चित हो सके।

३. षोध प्रविधि :-

प्रस्तुत षोध कार्य मुख्यतः द्वितीयक समकों के आधार पर किया गया है जिन्हें जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों, बैंक द्वारा संधारित विभिन्न लेखा पुस्तकों, षीर्ष बैंक व नाबाई द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों सहकारिता संबंधी विभिन्न पत्रिकाओं व सामाचार पत्रों से संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बैंक की हर शाखा से संबंधित ५०-५० हितग्राहियों का चयन वैद निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया तथा इन हितग्राहियों से साक्षात्कार के माध्यम से इनके ऋण उद्देश्य, ऋणराशि, ऋण की पर्याप्तता, ऋण लेने में हुई कठिनाईयाँ आदि कि जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही बैंक की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कर्मचारी, प्रबंधकों, प्रशासक व जनप्रतिनिधियों के विचारों को भी संकलित किया गया। संकलित समकों का विप्लेशन विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करते हुए षोध के संबंध में निश्कर्ष ज्ञात किए गए।

४. परिकल्पनाएं :-

इस षोध कार्य के संबंध में निम्न परिकल्पनाएं की गई थी :-

१. दीर्घकालीन कृषि ऋण की सुविधाओं से जिले के कृषक लाभान्वित हुए हैं।
२. ऋण प्रक्रिया जटिल है।
३. बैंक राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है।
४. जिले में शाखाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ है।
५. बैंक द्वारा प्रदा ऋणों में कई ऋण ऐसे हैं जो कालातीत हुए हैं तथा जिनकी अदायगी अभी तक लंबित है।

पंजीयन :-

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का पंजीयन सहकारी संस्थाएं अधिनियम के तहत होता

है क्योंकि ये बैंक भारतीय बैंकिंग अधिनियम से संचालित न होकर प्रांतीय सहकारिता अधिनियम के आधार पर संचालित होते हैं। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव का पंजीयन क्रमांक २२५४४४ दिनांक १३.०२.१९७५ है।

कर्मचारी प्रबंध :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में प्रबंधकीय व प्रशासकीय स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (महाप्रबंधक) होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन शाखा प्रबंधक, लेखापाल, पर्यवेक्षक आदि कार्य करते हैं। वर्तमान में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव में महाप्रबंधक के अधीन कुल २७ सेवायुक्त कार्यरत हैं जिनमें से ०७ मुख्यालय में व शेष २० बैंक की ४ शाखाओं में पदस्थ हैं।

संचालक मंडल :-

सहकारिता अधिनियम के तहत बैंक में एक संचालक मंडल का गठन निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। संचालक मंडल का निर्वाचित अध्यक्ष जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, के हाथों में बैंक की सत्ता होती है। बैंक का महाप्रबंधक संचालक मंडल का पदेन सचिव होता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष के निर्देशन व नियंत्रण में करता है। बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर प्रायः सत्तारूढ दल से संबंधित नेता ही आसीन होते हैं।

साधारण सभा :-

बैंक द्वारा वर्ष में एक बार सदस्यों की साधारण सभा आयोजित करना अनिवार्य होता है बैंक की वार्षिक साधारण सभा में निम्न विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं:-

१. अंतिम लेखा व लेखा परीक्षण की रिपोर्टों पर विचार

२. बैंक की उपविधियों में परिवर्तन

३. आगामी वर्ष की योजनाओं पर विचार जहाँ तक प्राधिकारों का प्रश्न है साधारण सभा सर्वोत्तम है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं।

अंशपूजी :-

बैंक की अंशपूजी को अ,ब,एवं स वर्ग के सदस्यों से एकत्र किया जाता है, जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वह अ वर्ग का सदस्य कहलाता है। इन्हे बैंक से ली जाने वाली ऋण राशि के ५ प्रतिशत के बराबर बैंक के अंश अनिवार्यतः क्य करन होते हैं। इस प्रकार कृषक बैंको के अंशों को क्य करके अ वर्ग का सदस्य बन गया है। अ वर्ग के सदस्यों को संचालकों के चुनाव में मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ब वर्ग के सदस्य वे होते हैं, जिनका अ वर्ग के सदस्य द्वारा ऋण हेतु गिरवी रखी हुई संपत्ति पर सहस्वामित्व हो। ब वर्ग के सदस्यों को ५ रु अंकित मूल्य का एक अंश अनिवार्य रूप से क्य करना होता है। इन्हे संचालक मंडल के चुनाव में मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है।

सर्वर्ग की सदस्यता राज्य शासन को प्राप्त होती है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर बैंक में अंशदान किया जाता है। अंशदान के फलस्वरूप बैंक के संचालक मंडल में चार व्यक्ति नामांकित करने का शासन को अधिकार होता है।

बैंक की अंश पूजी में अध्यायित वर्षों के दौरान विभिन्न वर्ग के सदस्यों के योगदान का विवरण निम्नानुसार रहा है-

सारणी क्रमांक - १

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव अंशपूजी में योगदान

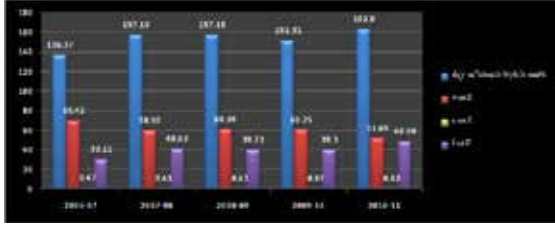
वर्ष कुल अंशपूजी

(लाख में) अंशदान प्रतिषत रूप में

अ वर्ग ब वर्ग स वर्ग

२००६-०७	१३६.३७	६९.४२	.४७	३०.११
२००७-०८	१५७.१९	५८.९६	.४१	४०.६३
२००८-०९	१५७.१८	६०.३४	.४३	३९.२३
२००९-१०	१५१.३१	६०.२५	.४५	३९.३०
२०१०-११	१६२.९०	५१.४९	.४२	४८.०९

स्रोत:- जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्षिक प्रतिवेदन २०१०-११



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विभाग बैंक की अंशपूजी में सर्वाधिक हिस्सा (योगदान) संदेव अ वर्ग के सदस्यों का ही रहा है दूसरा प्रमुख हिस्सा स वर्ग (राज्य घासन) का रहा है। ब वर्ग के सदस्यों का योगदान नगण्य है।

निक्षेप :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, द्वारा राष्ट्रीय बैंक की भंति अपने काउंटर पर बचत खाता, चालू खाता की जमाएं स्वीकार नहीं की जाती लेकिन पीएच बैंक की ओर से उन्हें निक्षेप प्राप्त करने के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया है जिसके फलस्वरूप जिला बैंक द्वारा निम्न योजनाओं के तहत निक्षेप स्वीकार किये जाते हैं।

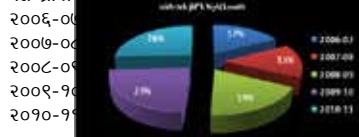


जिला बैंक निपेक्ष में संग्रहित राशियों को राज्य बैंक को पास ऑन कर देते हैं इस हेतु जिला बैंक को जमा राशि पर १ प्रतिशत कमिशन प्राप्त होता है बैंक द्वारा विगत वर्षों में संग्रहित निक्षेप राशियां निम्नानुसार रही हैं-

सारणी क्रमांक -२

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव प्राप्त जमाओं (निक्षेपों) का वितरण

वर्ष प्राप्त



स्रोत:- जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव का वार्षिक प्रतिवेदन (२०१०-२०११)

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा निक्षेप के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की गई है, इसकी सराहना पीएच बैंक ने भी की है।

पीएच बैंक के ऋण:-

बैंक द्वारा ऋणों की आपूर्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था में पीएच बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब किसी ऋण प्रकरण में जिला बैंक ऋण स्वीकृत करता है तो ऋण से संबंधित बंधक विलेख की प्रति पीएच बैंक को प्रेषित कर प्रतिपूर्ति राशि पीएच बैंक से प्राप्त कर लेता है, पीएच बैंक द्वारा इस दी गई राशि पर जिला बैंक से ब्याज वसूल किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव से अधिविकर्ष, बैंक की निधियों आदि के फलस्वरूप बैंक की कार्यशील पूंजी में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है।

ऋण प्रक्रिया :-

जिले का कोई भी कृषक जो सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रा. जनांदगांव से ऋण लेना चाहता है वह बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरकर, आवश्यक दस्तावेज नत्थी कर उसे बैंक में जमा करता है बैंक द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों के लिये रजिस्टर रख जाता है जिसमें प्राप्त आव.

ेदन पत्रों की तिथिवार प्रविष्टी कर उसी क्रम में कार्यवाही की जाती है।

आवेदन पत्र पूर्ण होने पर उसे मूल्यांकन हेतु मूल्यांकक को अग्रोशित किया जाता है। मूल्यांकक स्थल पर जा कर ऋण प्रकरण संबंधी सभी आवश्यक पहलुओं की गहन जांच पडताल कर अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप से अंतिम ५ दिन के अंदर जिला बैंक को प्रस्तुत करता है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक बंधक रखी गई भूमि की जांच रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकार्ड से करता है। तथा प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तथा यदि जिला बैंक को ऋण स्वीकृति के अधिकार प्राप्त नहीं है तो प्रकरण पीएच बैंक को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। पीएच बैंक इस पर अधिकतम १५ दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित कर देता है।

प्रकरण स्वीकृति के पश्चात् आवेदक को बैंक में बुलवाकर बंधक विलेख का निशपानन करवाया जाता है बंधक विलेख निशपानन के बाद बैंक अपनी निधियों से तुरंत ऋण वितरित कर बंधक विलेख पीएच बैंक को प्रेषित कर राशि प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है। ऋण हेतु आवेदन अस्वीकार किये जाने की दषा में उसके लिये कारण बैंक द्वारा आवेदक को संसूचित कर दिये जाते हैं।

प्रदत्त ऋण :-

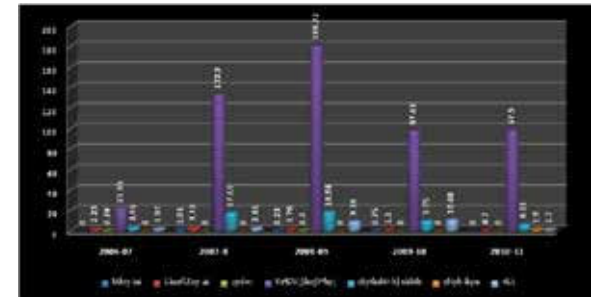
जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव द्वारा जिले के कृषकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु वितरित किये गये ऋणों का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:-

सारणी क्रमांक - ३

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव वितरित ऋणों का वर्षवार विवरण

ऋण प्रयोजन	वितरित ऋण					योग
	२००६-०७	२००७-०८	२००८-०९	२००९-१०	२०१०-११	
डीजल पंप	-	१.०१	२.३	२.५	-	१.४९
सबमर्सिबल पंप	२.५३	३.१९	१.७६	१.१०	०.७०	९.२८
नलकूप	०.२८	-	०.२०	-	-	.४८
ट्रेक्टर, पावरडीलर	२१.९५	१३२.९०	१८०.२२	९७.४१	९७.५०	५२९.९८
बैलजोडी, गाडी	३.४५	१७.६९	१८.५८	९.७५	६.११	५५.५८
मछली पालन	-	-	-	-	१.९०	१.९०
अन्य	१.९७	२.८१	९.१८	१०.६८	१.७०	२६.३४
योग	३०.१८	१५७.६०	२१०.१७	११९.१९	१०७.९९	६२५.०५

स्रोत:- जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्षिक प्रतिवेदन (२०१०-११)



उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अध्यायित वर्षों के दौरान बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजनों हेतु ६२५.०५ लाख रु के ऋण वितरित किये गये हैं। सर्वाधिक ऋण ट्रेक्टर प्रकरणों में ८४.७९; तथा सबसे कम ऋण वितरण ०.०७७; नल कूप प्रकरणों में रहा है।

ब्याज दरें :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव की ऋण वितरण हेतु ब्याज दरें अन्य बैंकों की तुलना में कम है तथा बैंक द्वारा निक्षेप योजनाओं पर दिया जाने वाला ब्याज १ वर्ष का ८.७%; तथा २ वर्ष का अधिकतम ९.२%; प्रति वर्ष है।

ऋणों की वसूली :-

बैंक द्वारा हितग्राही को जो ऋण वितरित किया जाता है उसमें से छूट अवधि तक तो कृषक से केवल ब्याज की राशि ही वसूल की जाती है। इसके पश्चात् ऋण की राशि पर ब्याज व मूलधन के आधार पर किफ्त निर्धारित कर वसूली की जाती है सामान्यतः कृषकों से वसूली हेतु उनके द्वारा उत्पादित खरीफ/रबी फसल को ध्यान में रखकर ३१ जनवरी व ३१ मई किफ्त चुकाने की तिथियां दी जाती हैं ताकि कृषक अपनी उपज का विक्रय कर बैंक की किफ्त का भुगतान आसानी से कर सकें बैंक में राज्य घासन की ब्याज अनुदान योजना लागू है जिसमें किसानों को पुर्व के ऋण पर ३- ब्याज पर ऋण वसूल किया जा रहा है।

लेकिन यह पाया गया कि इसके बावजूद भी कृषकों से ऋणों की वसूली में बैंक को अनेक बाध आओ का सामना करना पड़ता है। इसकी प्रमुख वजह सूखा, अतिवर्षा, ऋणों का दुरुपयोग, राजनीतिक दखलंदाजी पाई गई है।

कालातीत ऋण :-

किसी वर्ष के लिये ऋणकर्ता (कृषक) से प्राप्त होने वाली राशि जो निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक को प्राप्त नहीं हो पाती वह कालातीत ऋण कहलाती है। हर वर्ग के बैंक की भांति जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव भी कालातीत ऋणों की समस्या से ग्रस्त है।

अध्ययन अवधि में कालातीत ऋण औसतन ४४: रहे हैं। बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम १९९९वी धारा २३ व २६ के तहत एस चुकर्ताओं के विरुद्ध सम्पत्ति की जब्ती व नीलामी की कार्यवाही की गई है।

आय व्यय का अध्ययन :-

बैंक की आय व व्यय की मर्दों का गहन अध्ययन करते हुये लाभ हानि का विप्लेशणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

आय की मर्द :-

बैंक के आय की मुख्य मर्द निम्न है:-

1. वित्तीय ऋणों पर प्राप्त ब्याज
2. अमानत एवं अन्य पर प्राप्त ब्याज
3. अंशों पर लाभांश
4. अन्य प्राप्तियां

व्यय की मर्द :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव को अपने कार्यों के संचालन के लिये अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। व्यय की प्रमुख मर्द निम्न हैं:-

1. षीर्ष बैंक को चुकाया गया ब्याज
2. अमानत एवं अन्य पर दिया गया ब्याज
3. व्यवस्थापन व्यय
4. प्रशासनिक व्यय
5. निधि निर्माण/प्रावधान

अध्यायित वर्षों में बैंक के औसत व्यय २२३.०२ लाख रु प्रति वर्ष रहे हैं इसमें ६५.८५: तो केवल षीर्ष बैंक से ली गई ऋण राशि पर चुकाय गये ब्याज के हैं इस प्रकार व्ययों में सबसे ज्यादा भार इन चुकाए गए ब्याज का है इसी प्रकार अमानत व अन्य पर दिया गया मद का व्यय में हिस्सा १०.२६: व्यवस्थापन व्यय का २०.२२: प्रशासनिक व्यय का ३.६७: रहा है।

आय व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नांकित तालिका से बैंक के विभिन्न वर्षों के आय व व्यय की तुलना की जा सकती है:-

तुलनात्मक अध्ययन

सारणी क्रमांक :- ४ जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव आय व्यय का

वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	हानि
२००६-०७	१२१.६७	१४०.४५	१८.७८
२००७-०८	२२२.१२	२७४.७९	५२.६७
२००८-०९	२३२.००	३०४.००	७२.००
२००९-१०	१८७.००	३०४.००	११७.००
२०१०-११	३५२.३१	३९४.००	४१.६९

स्रोत:- जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्षिक प्रतिवेदन (२००६-०७ से २०१०-११)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के व्ययों की तुलना में आय हर वर्ष कम रही है जिसके फलस्वरूप बैंक लगातार हानि में चल रहा है।

बैंक से प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाले विभिन्न वर्गों यथा कृषक (अंशधारी), कर्मचारी प्रशासक, जनप्रतिनिधि से बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में विचारों संकलित करते हुये इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों को भी शामिल किया गया है।

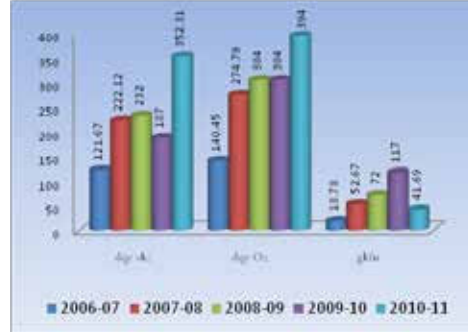
विभिन्न वर्गों से प्राप्त विचारों के आधार पर बैंक की कार्यप्रणाली की अनेक खामियां सामने आईं जैसे ऋण प्रक्रिया की जटिलता, षीर्ष बैंक पर अत्यधिक निर्भरता बैंक के कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप आदि। इन दोषों का निवारण किया जाना बैंक की प्रगति के लिये आवश्यक है।

समस्याएं :-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ है कि यह बैंक अनेक समस्याओं से जुड़ा रहा है। प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:-

- बैंक एक लंबे समय से स्टाफ की कमी से जुड़ा रहा है। भर्ती प्रक्रिया वर्षों से बंद पड़ी है।
- तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में बैंक के तकनीकी कार्य गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं।
- बैंक सेवायुक्तों के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों की भांति ७ घंटे कार्य किया जाता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों की तुलना में वेतन व सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं।
- ग्राहकों की यह शिकायत रहती है कि बिना लेन देन के यहां कोई कार्य नहीं होता।
- बैंक से ऋण लेने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया बहुत लंबी व जटिल होती है, जिसके कारण कई कृषक ऋण लेने का विचार ही त्याग देते हैं।
- बैंक की स्थापना १९७५ में हुई थी। स्थापना के इतने वर्षों बाद भी बैंक का अपना भवन नहीं है। आज भी बैंक मुख्यालय व शाखाएं किराये के भवनों में संचालित हो रही है।
- बैंक की जिले में ४ शाखाएं हैं जो जिले के विपणन भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए काफी कम हैं। शाखाओं की कमी के कारण बैंक का व्यवसाय आभासीत प्रगति नहीं कर पाया है।
- जिला बैंक को अनेक कार्यों हेतु षीर्ष बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। जिससे बैंकिंग कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है।
- बैंक सेवायुक्तों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य में नहीं है। राज्य के बाहर भेजने पर खर्च अधिक आता है।

- बैंक के कालातीत ऋणों ने बैंक को वित्तीय संकट में डाला हुआ है।
- वित्त व स्टाफ की कमी के कारण बैंक द्वारा शाखाओं व ऋण के उपयोगीकरण की जांच नहीं हो पा रही है।
- वित्तीय समस्याओं के चलते बैंक को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव से उंची ब्याज पर अधिविक्रय लेने विवश होना पड़ता है।
- बैंक के समक्ष एक गंभीर समस्या उसके कार्यों में बढ़ता हुआ राजनैतिक हस्तक्षेप है।
- बैंक की संचालन लागते निरंतर बढ़ रही है। जिसके कारण बैंक को प्रतिवर्ष हानि का सामना करना पड़ रहा है।



निष्कर्ष व सुझाव :-

प्रस्तुत षोध में मूलरूप से बैंक की कार्यप्रणाली एवं बैंक के नियमों का गहन अध्ययन कर उनका जिले के कृषकों की आय व प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की गई है। इससे पता चला है कि बैंक ने किस प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रयास किये तथा कौन-कौन सी कमियां से बैंक उबर नहीं पाया है।

बैंक के निक्षेप उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। अंशधारी में भी निरंतर वृद्धि हुई है। कृषकों की रुचि अब कृषि के आधुनिक साधनों में बढ़ी है। कृषकों द्वारा उन्नत कृषि व अपनी आय में वृद्धि हेतु ट्रेक्टर का इस्तेमाल निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजनांदगांव द्वारा कृषकों को ट्रेक्टर हेतु अधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष २००६ से २०११ की अवधि में बैंक द्वारा कृषकों को ट्रेक्टर हेतु ५२९.९८ लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं।

ट्रेक्टर के अलावा बैंक द्वारा कृषकों को अन्य विविध प्रयोजनों जैसे पंप सेट, बैलजोडी गाड़ी, हेतु भी निरंतर ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जिससे जिले के कृषकों को प्रगति के अवसर उपलब्ध हुये हैं।

बैंक के वित्तीय ऋणों से कृषकों की आय में वृद्धि व प्रगति का जब जांचा गया तो पता चला कि बैंक के ऋण निवेश से जहाँ कुछ क्षेत्रों में कृषकों की आय में वृद्धि हुई। वहीं कुछ क्षेत्रों में बैंक का ऋण निवेश निष्फल भी रहा है। इसके कारणों की जांच भी की गई है। बैंक के ऐसे भी ऋण निवेश देखे गये जिससे कृषक की आय में वृद्धि तो हुई लेकिन कृषक द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते किष्टों की अदायगी नहीं की गई।

ऋणी सदस्यों की घटती संख्या

बैंक के ऋणी सदस्यों की संख्या जहाँ वर्ष २००६-०७ में ५०७७ थी, वहीं २०१०-११ में यह ५५२७ ही है। जिससे जिले के कृषकों के इस बैंक से जुड़ाव कम होने के संकेत मिलते हैं इसकी वजह निम्नानुसार पाई गई है।

बैंक की जिले में मात्र ५ (अब ४) शाखाएं हैं। जिले के विपणन भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यह काफी कम है। दूर-दराज क्षेत्र के कृषक दूरी की वजह से इस बैंक से नहीं जुड़ पाये हैं। बैंक द्वारा केवल दीर्घकालीन ऋण दिये जाने के कारण जिले के अधिकांश ऐसे कृषक जिन्हें अल्पकालीन व मध्यकालीन कृषि ऋणों की आवश्यकता पड़ती है वे इस बैंक से नहीं जुड़ पाते हैं। दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता वाले बड़े कृषक तो बैंक की योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। लेकिन लघु कृषक इस बैंक से समुचित मात्रा में नहीं जुड़ पाये हैं। जिससे लघु कृषकों व बैंक के बीच एक रिक्तता की स्थिति आ गई है। जिसका फायदा साहूकारों द्वारा आज भी उठाया जा रहा है। आज भी साहूकारों की महत्ता कम नहीं हुई है। साहूकारों की उँची ब्याज दरों का बावजूद कृषकों का उनके पास जाना बैंक की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वस्तुतः कृषकों की अधिका, बैंक की ऋण प्रक्रिया की जटिलता, ५ प्रतिशत अंशधारी की अनिवार्यता आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ऋण राशि की अनुपलब्धता, सेवायुक्तों द्वारा पैसों की मांग आदि ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से छोटे कृषक बैंक का रुझ करना पसंद नहीं करते।

ईरादतन और गैर ईरादतन चुकर्ताओं के कारण बढ़ते कालातीत ऋण, बढ़ती संचालन लागते, आर्यों में अपेक्षित वृद्धि के अभाव, षीर्ष बैंक का बढ़ता ऋण भार आदि ने बैंक को घोर वित्तीय संकट में डाल दिया है।

बैंक सेवायुक्तों के लिये प्रशिक्षण अवसरों की कमी उन्हें छठे वेतनमान का लाभ न मिलना, ७ घण्टे की इयूटी षीर्ष पदों पर पदोन्नति के अवसरों के न होने के कारण बैंक सेवायुक्तों में निराशा व्याप्त है। ऐसी स्थिति में उनसे बैंक की प्रगति के लिये समर्पित भाव से काम करने की आशा करना व्यर्थ है।

इस प्रकार बैंक न तो कृषकों के सच्चे मित्र के रूप में अपनी पहचान बना सका है न ही अपने सेवायुक्तों को संतुष्ट कर सका है। प्रतिवर्ष घाटा होना इस बैंक की पहचान बन गई है। इन दशाओं में बैंक की प्रगति की आशा करना व्यर्थ है।

बैंक की समस्याओं को ज्ञात कर उन्हें सुलझाने की दिशा में कुछ प्रयास यदि किये गये हो तो

बैंक की यह दषा न होती।

प्रस्तुत षोध में बैंक की कार्यप्रणाली के गहन अध्ययन के उपरान्त इसकी ज्ञात समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

बैंक की कार्यदषा में सुधार हेतु प्रस्तुत सुझाव निम्नानुसार हैं :-

- बैंक में रिक्त पडे पदों पर तत्काल भर्ती की जानी चाहिए। भर्ती करते समय बी.एस.सी. कृषि व बी.ई. मेकेनिकल पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि बैंक में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी भी दूर हो सके।
- ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
- बैंक को ऋण वितरण कार्य में छोटे कृषकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए ५ प्रतिषत अंशपूँजी क्य करने की अनिवार्यता वाली षर्त को षिथिल करते हुए इसमें कुछ छूट दी जानी चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तों का वेतनमान अत्यधिक कम है जो जीवन निर्वाह के लिए अपर्याप्त है। अतः इनमें षीघ्र ही उचित व आवष्यक संषोधन किया जाना चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तों हेतु उचित प्रषिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- बैंक में राजस्व रिसाव को रोकने व लागत नियंत्रण जैसे विशयों पर कर्मचारियों को सघन प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए।

- ऋण वितरण करते समय परियोजना का मूल्यांकन बडी सावधानी से करना चाहिए ताकि बैंक का यह ऋण वितरण निःफल निवेश न हो सके।
- कृषक द्वारा ऋण लिये जाने के पष्वात् ऋण प्रयोजन की पूर्णता हेतु कृषक को यदि पुनः ६ इन की आवष्यकता पडे तो बैंक द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म अध्ययन कर आवष्यकतानुसार ६ इन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कृषक साहूकारों के वंगूल में न फंस सकें।
- बैंक ऋण वृककर्ताओं की सूची समाचार पत्रों में प्रकाषित करने का प्रावधान बैंक की उपविधियों में किया जाना चाहिए। जिले के ९ विकास खण्डों में मात्र ४ में ही बैंक की षाखाएँ हैं, षेश ५ विकास खण्डों में भी बैंक की षाखाएँ खोली जानी चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तों का ग्राहकों (कृषकों) से व्यवहार स्वामियों की तरह नहीं बल्कि सेवक (मित्र) की भांति होनी चाहिए।
- बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु स्वयं के वित्तीय स्रोत विकसित करने चाहिए।
- जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसकी षीर्ष बैंक पर निर्भरता समाप्त की जानी चाहिए।
- बैंकिंग कार्यों को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु संचालक मंडल के चुनावों में राजनैतिक पार्टी से सम्बद्धता रखने वालों के चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- उपरोक्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल करने से बैंक की स्थिति में निःसंदेह आषाजनक सुधार आएगा, जिससे बैंक व जिले के कृषक दोनों ही लाभान्वित होंगे।

REFERENCES

१. पंत जे.सी. "व्युषिट अर्थषास्त्र" द २. मदनलाल जिंदल "छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम १९६०", द (प्रकाषक: राजकमल पब्लिकेषन्स, इन्दौर- २००४) द ३. डॉ.राधेष्याम द्वि वेदी, २००१, "मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक", कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन तथा उनकी कार्य स्थिति) नियम १९८३ द ४. माथुर, गुप्ता "सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास अग्रवाल" द ५. डॉ. प्रभाकर पाण्डे "छत्तीसगढ के आर्थिक विकास में सहकारी अधिकोशो की भूमिका" द ६. श्री द.प्र.कन्नोजि "किसानों का सहायक मित्र सहकारी भूमि विकास बैंक" द ७. केषव सिंह "कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियां" द ८. डॉ.जयंती प्रसाद नोटियाल "कृषित्तर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका" द ९. बैंक ऋण वसुली प्रबंध विविध आयाम-ष्यामलाल गौड, डॉ. दलसिर यादव द १०. ऋण मैन्युअल-म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल द ११. पी.डी.माहेष्वरी, व्ही.डी.जोषी "बैंकिंग एवं राजस्व" द पत्रिकाएं द १. योजना द २. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदागांव के वार्षिक प्रतिवेदन २००६-२०११ द ३. कृषक जगत द ४. उद्यमिता द ५. सहकारी सुमन द ६. सफलता की कहानी, कृषकों की जुबानी छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।